भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 796
(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष निवेश मंच'

796: श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री गिरीश भालचंद्र बापट:
श्री चंद्र शेखर साहू:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य निवेश मंच विकसित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या हाल ही में एनआईआईएफ और जापान बैंक फोर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
(ङ) पिछले कुछ वर्षों में एनआईआईएफ द्वारा क्या प्रगति की गई और उन क्षेत्रों तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें अब तक ऐसी निधियों से निवेश की पहचान की जा चुकी है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) एवं (ङ): जी, हां । राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ), भारत सरकार, वैश्विक निवेशक बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और घरेलू संस्थानों के बीच एक सहयोगी निवेश मंच के रूप में स्थापित किया गया है। एनआईआईएफ के फंड में (i) वैश्विक निवेशकों जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए), ऑस्ट्रेलियनसुपर, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी), ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स, टेमासेक, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (यूएस डीएफसी) (ii) एशियन विकास बैंक (एडीबी), एशियन अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) जैसे एमडीबी शामिल हैं, और (iii) घरेलू वित्तीय संस्थान जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक लाइफ इंश्योरेंस से निवेश है। वर्तमान में एनआईआईएफ के पास तीन नामत:- मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक ऑपर्च्युनिटीज फंड जिन्हें 16 कंपनियों में निवेश किया है जिनमें बंदरगाह और लाजिस्टिक, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़के, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं और विनिर्माण इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। एक इंडिया जापान फंड के माध्यम से भारत में कई क्षेत्रों में निवेश की सुविधा के लिए नवंबर, 2022 में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

*****